



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश भी दिए।

‘रोडवेज ड्राइवर, कंडक्टर व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सेमीनार आयोजित करें’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने परिवहन, सड़क सुरक्षा विभाग व रोडवेज की समीक्षा बैठक ली

जयपुर, 30 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ , सुरक्षित एवं सुविधायुक्त बनाने के लिए लक्ष्यनिर्धारित करके कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कार वाले भी बसों में यात्रा के लिए प्रेरित हों।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए।

- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करायें कि कार वाले भी बस में यात्रा करने के लिए प्रेरित हों।
- उन्होंने कहा, ओवर लोड व ओवर स्पीड वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही व निगरानी होनी चाहिए।

उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करे। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन और सरस उत्पाद उपलब्ध कराने का नवाचार किया जाए। उन्होंने

प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों में कैमरे और जीपीएस स्थापित करें और लोक परिवहन बसों का भी कलर निर्धारण करें।

शर्मा ने पद दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों, ओवरलोड और ओवरस्पीड वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

और निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन परमिट जारी करने से पहले रूट निर्धारण करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, राजकीय कार्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद बैरवा सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

“हम पहलगाम की घटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सरहद पर अतिरिक्त सेनाएं तैनात कर दी थीं। संघर्ष के बाद, सार्वजनिक रूप से बोलने वाले पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठतम अधिकारी जनरल मिर्जा ने कहा, “हम करीब-करीब 22 अप्रैल की स्थिति पर वापस आ गये हैं। – – हम उस स्थिति पर पहुंचने वाले हैं, वैसे हमें उस स्थिति पर अब तक पहुंच जाना चाहिए था।”

जनरल मिर्जा, जो इस समय “शांगरी-ला डायलॉग” फोरम में शामिल होने के सिलसिले में सिंगापूर में हैं, ने कहा कि इस संघर्ष में, न्यूक्लियर हथियारों की तरफ कदम भले ही नहीं बढ़े हों, लेकिन स्थिति बहुत खतरनाक थी।

उन्होंने कहा, “इस बार कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसी भी समय किसी भी प्रकार के गलत रणनीतिक अनुमान की संभावना खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि जब संकटपूर्ण स्थिति होती है,

उस समय प्रतिक्रियाएं भिन्न प्रकार की होती हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इस बार की लड़ाई कश्मीर, जो हिमालय की गोद में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न क्षेत्र है, की जमीन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का कश्मीर के कुछ-कुछ हिस्से पर शासन है, लेकिन दोनों ही देश पूरे कश्मीर पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन किसी ने भी किसी गंभीर नुकसान की बात स्वीकार नहीं की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर भारत पर फिर से हमले किये गये तो सीमा पार के “आतंकी ठिकानों” को निशाना बनाया जाएगा।

दोनों देशों के बीच तीन बड़े युद्ध हुए हैं, जिनमें दो कश्मीर को लेकर ही

हुए हैं, वैसे तो अनेक सशस्त्र झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों ही देशों का जन्म 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश भारत से ही हुआ है।

भारत कश्मीर में विद्रोह का आरोप पाकिस्तान पर लगाता है, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई और उसमें अब तक दसियों हजार लोग मारे गये हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वह तो आत्म-निर्णय की दिशा में बढ़ रहे कश्मीरियों को केवल नैतिक, राजनैतिक एवं कूटनीतिक समर्थन एवं सहयोग देता है।

मिर्जा ने कहा, “भविष्य के लिहाज से, इन दोनों ही पड़ोसी न्यूक्लियर ताकतों के बीच और ज्यादा खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की संभावना बढ़ गई है, और फिर यह संघर्ष केवल विवादित भूभाग तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लेगा। यह बहुत ही खतरनाक संकेत है।”

“सिंदूर” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
परिस्थितितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है। जमानत याचिका में कहा गया कि मामले की एफआईआर में नामजद आरोपियों में से 23 लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दी है। जबकि अदालत के समक्ष पूर्व में उनकी मामलों में लिखता बताई गई थी और अदालत ने उन सभी को जमानत का लाभ दिया था। मामले में एसटी आयोग की जांच में भी पुलिस

पर आरोप लगे हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जमानत का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से जीए राजेश चौधरी ने कहा कि अदालत ने आरोपी की गत 14 फरवरी को जमानत याचिका खारिज की थी। उसके बाद आरोप पत्र पेश होने के बाद आरोपी पर चार्ज नहीं लगे हैं। ऐसे में जमानत याचिका को खारिज किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

‘वर्ष 2026 के अंत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बावजूद राम दरबार को दर्शनार्थियों के लिये खोला नहीं जायेगा क्योंकि इससे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है मगर सभी मूर्तियों की विधिवत पूजा अर्चना शुरु हो

जायेगी। उन्होने कहा कि देवोत्थान एकादशी के बाद भगवान विष्णु के शेषावतार की प्राण प्रतिष्ठा का एक और कार्यक्रम हो सकता है। मंदिर निर्माण अगले साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है जो विशाल परिसर के साथ अपने भव्य रूप में होगा।

कांग्रेस ने शशि थरूर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
द्वारा प्रतिनिधिमंडल के लिए चुने गए नाम पर आपत्ति जताई और कहा कि युसुफ पठान प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, तो सरकार ने उनकी बात मान ली। इससे मनमोदी को अपने नंबर दो नेता, अभिषेक बनर्जी को नामित करने का मौका मिल गया। इसके विपरीत, कांग्रेस ने थरूर को टीम में शामिल होने की स्वीकृति नहीं दी, बल्कि उसने कहा कि यह पूरी कवायद प्रधानमंत्री मोदी को उन कठिन हालातों से दूर रखने के लिए की जा रही है, जिनका उत्तर प्रधानमंत्री से मांगा जा रहा है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने स्वीकार किया कि अगर सरकार ने शुरुआत में ही अभिषेक बनर्जी का नाम प्रस्तावित

- पर, शशि थरूर की ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में की गई, अमेरिका की यात्रा का कांग्रेस कोई लाभ नहीं उठा पायी।

किया होता, तो ममता कोई विवाद खड़ा ही नहीं करतीं। अभिषेक बनर्जी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तुणमूल कांग्रेस भी राष्ट्रवाद पर उतनी ही आक्रामक हो सकती है जितनी कि भाजपा। टोक्यो में उन्होंने कहा, “अगर

आतंकवाद एक पागल कुत्ता है, तो पाकिस्तान उसका गंदा खवाला है। हमें पहले इस जंगली खवाले को काबू में करना होगा- नहीं तो यह और भी पागल कुत्ते पैदा करता रहेगा।” अभिषेक के इस बयान का तुणमूल कांग्रेस खूब प्रचार कर रही है। टोक्यो में अभिषेक ने रास बिहारी बोस के स्मृति-स्थल का दौरा किया और उसकी उपेक्षित और जीर्ण-शीर्ण हालत के मुद्दे को उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने हमारे राजदूत और टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि इस अद्वितीय वीर को वह सम्मान मिले जिसके वह वास्तव में हकदार हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व इस अभियान से बार-बार दूरी बनाता रहा है, यह कहते हुए कि इससे मतदाता धुंवीकृत हो सकते हैं। थरूर का स्वतंत्र रख उनके सत्ताधारी दल के प्रति बढ़ते झुकाव की अटकलों को और तेज कर रहा है। कांग्रेस की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब वरिष्ठ पार्टी नेता और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सलमान खुशींद ने अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान सुर्खियां बटोरीं। प्रमुख बुद्धिजीवियों से बातचीत के दौरान एक चौकाने वाले बयान में खुशींद ने अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का समर्थन किया। जबकि यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसका कांग्रेस परंपरागत रूप से विरोध करती रही है।

गाज़ा में अस्थायी युद्ध विराम पर इज़रायल ने सहमति दी

वाशिंगटन, 30 मई। अमेरिका के वाइट हाउस ने कहा कि इजरायल ने गाज़ा में 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में, पुष्टि की कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव वित्कोफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमसा को युद्ध विराम प्रस्ताव सौंपा है, जिसका इजरायल ने समर्थन किया है। लेविट ने कहा, हमसा को भेजे जाने से पहले इजरायल ने इस प्रस्ताव पर

- अमेरिका ने बताया कि यह युद्ध विराम 60 दिन का होगा।

हस्ताक्षर कर दिए थे। मैं यह भी पुष्टि कर सकता हूं कि वे चर्चाएं जारी हैं, और हमें उम्मीद है कि गाज़ा में युद्ध विराम होगा ताकि हम सभी बंधकों को घर वापस ला सकें। सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, एक इजरायली अधिकारी और मामले से परिचित एक अमेरिकी सूत्र ने पुष्टि की कि प्रस्तावित समझौते में न केवल 60-दिवसीय युद्ध विराम शामिल है, बल्कि 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के अवशेषों को रिहा करने की योजना भी शामिल है।

हिन्दुस्तान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कर्नाटक के मंत्री ने यह भी अफसोस जताया कि इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, 2022-23 में रक्षा कॅॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को आवंटित किया गया, कर्नाटक को नहीं। योगदान और योग्यता के आधार पर इसका हकदार कर्नाटक है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या “पूर्ण” हुई

तीन न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है

- सी.जे.आई. बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में तीन नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई।

मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के और न्यायमूर्ति चंद्रकर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। अहमदाबाद के मांडवी-कच्छ में 23 मार्च, 1965 को वकीलों के परिवार में जन्मे न्यायमूर्ति अंजारिया के पिता भी न्यायपालिका में थे। अंजारिया अगस्त 1988 से वरिष्ठ अधिवक्ता एस एन शेलत के चैंबर में शामिल होकर गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और वे संवैधानिक मुद्दे और सभी श्रेणियों के सिविल मामलों, श्रम और सेवा से जुड़े मामलों में वकालत कर चुके हैं। न्यायमूर्ति अंजारिया ने 25 फरवरी, 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की कोलौजियम ने 26 मई 2025 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मुहर के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायमूर्ति अंजारिया, न्यायमूर्ति बिश्नोई और न्यायमूर्ति चंद्रकर को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के अधिसूचना जारी की थी। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद की शपथ लेने से पहले न्यायमूर्ति अंजारिया कर्नाटक उच्च न्यायालय के

जनवरी, 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सात जनवरी, 2015 को राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने पांच फरवरी, 2024 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य शुरू किया।

न्यायमूर्ति चंद्रकर का जन्म सात अप्रैल, 1965 को हुआ था। मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता बी एन नाइक के मार्गदर्शन में उन्होंने वकालत शुरू की, जिन्हें बाद में न्यायपालिका में पदोन्नत किया गया। न्यायमूर्ति चंद्रकर 1992 में नागपुर चले गए और विभिन्न न्यायालयों में वकालत की और अलग-अलग प्रकृति के मामलों को सफलतापूर्वक संभाला। उन्हें 21 जून, 2013 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। बाद में वे वहां चीफ जस्टिस बने।

पहलगाम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
ऐशान्या और शुभम के पिता की आंखों से आंसू निकल आए, जिन्हें देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें ढ ढस सं बंधाया। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन ‘सिंदूर’ रुका नहीं है, बल्कि यह आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकारी उनके साथ है और आगे भी मुलाकात होती रहेगी। शुभम द्विवेदी के परिवारों की नखल एसडीएम की देखरेख में कार से चेकरी एयरपोर्ट लाया गया था।

गृह मंत्री शाह ने पुंछ का दौरा किया

शाह पुंछ में पाक गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मिले और नियुक्ति पत्र दिए

- शाह ने कहा, सरकार प्रभावित परिवारों के लिए जल्दी ही एक अलग पैकेज की घोषणा करेगी।
- ज्ञातव्य है कि पाक गोलीबारी में पुंछ सर्वाधिक प्रभावित हुआ, यहां 14 नागरिक मारे गए।

इलाके में ज्यादा जनहानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार सीमावर्ती इलाकों में और बंकर बनाएंगी।

पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि राहत और नौकरियां आपके द्वारा झेले गए दर्द और नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती हैं। आपने अपने प्रियजनों को खो दिया है। आपका कश्मीर सरकार, भारत सरकार और राष्ट्र की भावनाएं इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से जुड़ी हुई हैं। सरकार जल्द ही गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए एक अलग पैकेज की घोषणा

करेगी। उन्होंने कहा, हम पहलगाम आतंकवादी हमले और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा नागरिक क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, स्कूलों पर हमले की निंदा करते हैं, जिसमें पुंछ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी में जुड़वां बहनों समेत कम से कम 14 नागरिक मारे गए हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बावजूद जम्मू-कश्मीर में विकास कार्य नहीं रुकेंगे। मैं पुंछ के लोगों और उसके

सेना प्रमुख द्विवेदी ने कश्मीर में सेना चौकियों का दौरा किया

जम्मू, 30 मई। सेना प्रमुख जनरल उंपेंद्र द्विवेदी ने आज यहां जम्मू-कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में अग्रिम इलाकों और चौकियों का दौरा कर क्षेत्र में स्थित विभिन्न सैन्य इकाईयों की परिचालन तत्परता का आकलन किया। जम्मू स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने यहां कहा कि इस दौरान सेना प्रमुख को मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य और नियंत्रण रेखा पर सेना की परिचालन गतिशीलता के बारे में जानकारी दी गई जिससे मौजूदा रणनीतिक माहौल की व्यापक तस्वीर सामने आई। इस बीच सेना प्रमुख ने सैनिकों के साथ बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की और सभी रेजों को उनकी व्यवसायिका, समर्पण और दृढ़ ता के लिए शाबाशी दी।

1 5 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

नयी दिल्ली, 30 मई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में विभिन्न वर्ग की 15 नर्सों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया।

पुरस्कृत नर्सों में एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) वर्ग में अंडमान निकोबार की रेवा राणी सरकार, आंध्र प्रदेश की वलिवेती सुभावती, दादर-नगर हवेली एवं दमन-दीव की सरोज फकीरभाई पटेल, लक्षद्वीप की रंजिया बेगम पीबी और महाराष्ट्र की सुजाता अशोक बागुल , एलएचवी (लेडी हेल्थ विजिटर) वर्ग में असम

की बीना पानी डेका, नर्स वर्ग में अरुणाचल प्रदेश की किजुम सोरा कारगा, दिल्ली की हिम्मल अरोड़ा और मेजर जनरल शीना पी डी, कर्नाटक की डॉ॰ बानू एमआर, मणिपुर की लीमापोकपम रंजीता देवी, मिजोरम की वी लालमंगई, पुडुचेरी की एलएस मणिमोझी, तमिलनाडु की के अलामेलु मंगयारकरसी और पश्चिम बंगाल की डॉली बिस्वास शामिल हैं।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं पश्चिम बंगाल की इसका उद्देश्य उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान देना है।